M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2022

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 5
Total No. of Questions : 5

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 10
No. of Printed Pages : 10

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न–पत्र

ARTICLE & SUMMARY WRITING
लेख और सारांश लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Please, adhere to the words limit of answers as specified in question paper and such violation may lead to minus marking.

   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of question paper, Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका/अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any mistake either printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

   किसी प्रश्न या प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि होने की दशा में, प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.1- Write an article either in English or in Hindi on the following *Social* topic :
निम्नलिखित *सामाजिक* विषय पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लेख लिखिए: –10

Hate Speech: in the light of freedom of expression

अभद्र भाषा : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आलोक में

Q.2- Write an article either in English or in Hindi on the following *legal* topic:
निम्नलिखित *विधिक* विषय पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लेख लिखिए: –10

God is not a juristic person, but idol is.

ईश्वर विधिक व्यक्ति नहीं है, परंतु मूर्ति है।

Q.3- Summarize the following legal passage into English (in around 1/3rd words of the passage given) :-

निम्नलिखित विधिक गद्यांश का अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण कीजिए (दिये गये गद्यांश के लगभग 1/3 शब्दों में) :– –20

This Court while considering the provisions of Sections 156(3), 169, 178 and 190 of the Code of Criminal Procedure, 1973 held that there is no power, expressly or impliedly conferred under the Code on a Magistrate to call upon the police to submit a charge-sheet, when they have sent a report under Section 169 of the Code, that there is no case made out for sending up an accused for trial. The functions of the magistracy and the police are entirely different and the Magistrate cannot impinge upon the jurisdiction of the police, by compelling them to change their opinion so as to accord with his view. However, he is not deprived of the power to proceed with the matter. There is no obligation on the Magistrate to accept the report if he does not agree with the opinion formed by the police.

The report may conclude that an offence appears to have been committed by a particular person or persons and in such a case, the Magistrate may either (1) accept the report and take cognizance of the offence and issue process, or (*2*) may disagree with the report and drop the proceeding, or (3) may direct further investigation under Section 156(3) and require the police to present final report.

The report on the other hand may state that according to the police, no offence appears to have been committed. When such a report is placed before the Magistrate he again has the options of adopting one of the three courses open, that are (1) he may accept the report and drop the proceeding; or (2) he may disagree with the report and take a view that there is sufficient ground for proceeding further, take cognizance of the offence and issue process; or (3) he may direct further investigation to be made by the police under Section 156(3).

The position is, therefore, now well settled that upon receipt of a police report under Section 173(2), a Magistrate is entitled to take cognizance of an offence under Section 190(1)(*b*) of the Code even if the police report is to the effect that no case is made out against the accused. The Magistrate can take into account the statements of the witnesses examined by the police during the investigation and take cognizance of the offence complained of and order issue of process against the accused. Section 190(1)(*b*) does not lay down that a Magistrate can take cognizance of an offence only if the investigating officer gives an opinion that after investigation a case against the accused has been made out.

The Magistrate can ignore the conclusion arrived at by the investigating officer and independently apply his mind to the facts

emerging from the investigation and take cognizance of the case, if he thinks fit, exercise his powers under Section 190(1)(*b*) and direct issue of process against the accused. The Magistrate is not bound in such a situation to follow the procedure laid down in Sections 200 and 202 of the Code for taking cognizance of a case under Section 190(1)(*a*) though it is open to him to act under Section 200 or Section 202 also.

The informant is not prejudicially affected when the Magistrate decides to take cognizance and to proceed with the case. But where the Magistrate decides that sufficient ground does not subsist for proceeding further and drops the proceeding or takes the view that there is material for proceeding against some and there are insufficient grounds in respect of others, the informant would certainly be prejudiced as the first information report lodged becomes wholly or partially ineffective.

Where the Magistrate decides not to take cognizance and to drop the proceeding or takes a view that there is no sufficient ground for proceeding against some of the persons mentioned in the first information report, notice to the informant and grant of opportunity of being heard in the matter becomes mandatory. As indicated above, there is no provision in the Code for issue of a notice in that regard. The question relating to issue of notice and grant of opportunity as afore described is of general importance.

Q.4- Translate the following 30 Sentences into English :-
निम्नलिखित 30 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :- **–30**

(1) जब किसी कानून का आशय आज्ञापक होता है, तब वह नकारात्मक आदेश से आच्छादित होता है।

(2) प्रतिषेधात्मक या नकारात्मक शब्द विरलता से ही, यदि कभी उनका प्रयोग किया जाये, निदेशात्मक होते हैं।

(3) एक मामले पर विचार करते समय किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य में प्रकट हुए लोपों, विरोधाभासों या विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ दे सकता है।

(4) समाचार पत्र में प्रकाशन किये जाने सहित विभिन्न तरीकों से प्रत्यर्थी को नोटिस तामील कराये जाने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित होने में असफल रहा है।

(5) उन मुकदमेबाजों को, जिन्होंने मिथ्या अभिवचन और कूट रचित दस्तावेजों के बल पर, अंतरिम व्यादेश अभिप्राप्त किया है, पर्याप्त रूप से दण्डित किया जाना चाहिये।

(6) समाज में महिला की मर्यादा का आदर करना सभ्य समाज की मूल सभ्यता को दर्शाता है।

(7) किसी अधिवक्ता द्वारा वृत्तिक सदाचार के सिद्धांतों का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है।

(8) आठ वर्ष की ऐसी कन्या के साथ पाश्विक व्यवहार किया गया, जिसके खेलने कूदने की आयु थी और उसकी भौतिक गरिमा और निष्कलंकता बर्बाद हुई।

(9) अब यह सुस्थापित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 17 के अधीन किसी साक्षी को पुनः बुलाने की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या वाद के किसी पक्षकार द्वारा फाईल किए गए आवेदन के आधार पर किया जा सकता है।

(10) न्यायालयों को वह कार्य करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, जो अन्तर्निहित शक्तियों के तात्पर्यित प्रयोग द्वारा विधि या संहिता के अनुसार प्रतिषिद्ध हो।

(11) न्यायिक अधिकारियों के विरूद्ध मिथ्या अभिकथन करने और उन्हें अपमानित करने संबंधी खतरनाक प्रवृत्ति को कठोरता से रोकने की आवश्यकता है।

(12) विज्ञान के इस युग में हमें ऐसे विधिक सिद्धांतों की रचना करनी चाहिए, जो विज्ञान और विधि की दृष्टि से ठोस हों।

(13) उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय या दिये गये आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(14) राज्य के विधान–मण्डल के सदन का या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारीवृंद होगा।

(15) प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिये

दण्ड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियॉ होंगी।

(16) जहॉ नमूना उस परिसर से लिया जाता है, जिस परिसर में औषधि या प्रसाधन सामग्री विनिर्मित की जा रही है, वहॉ नमूने को केवल तीन प्रभागों में विभक्त करना आवश्यक होगा।

(17) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है।

(18) अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से सम्पर्क में ना आये।

(19) विशेष न्यायालय, मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता–पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है।

(20) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को महिलाओं के समानता, प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण समझा गया है।

(21) बहुधा न्याय के संदर्भ में कहा जाता है कि न्याय का होना ही आवश्यक नहीं है वरन् यह भी आवश्यक है कि जनता को यह प्रतीत भी हो कि न्याय हुआ है।

(22) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, जो यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं, किंतु अन्यथा सुसंगत है।

(23) न्यायालय समन निकालने के समय यह अवधारित करेगा कि क्या वह केवल विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये होगा या वाद के अंतिम निपटारे के लिये होगा।

(24) यह न्यायालय की अधिकारिता के भीतर नहीं है कि जिस प्रतिवादी के विरूद्ध किसी अनुतोष का दावा नहीं किया गया है उसके विरूद्ध अनुतोष की मंजूरी दी जाये।

(25) परिवादी का एक खुले खेत में प्रवेश करना जिसका अपीलार्थीगण के कब्जे में होना तात्पर्यित है, गृह अतिचार का प्रकरण नहीं हो सकता।

(26) अभिलेख, यदि साध्य हो तो, उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परीक्षा की जाती है, यदि यह साध्य न हो तो न्यायालय की भाषा में होगा।

(27) अभियुक्त को सदैव उसके विरूद्ध विरचित किये गये आरोपों से अवगत कराया जाना चाहिये, ताकि वह अपना साक्ष्य उचित रूप से प्रस्तुत कर सके।

(28) ऐसे हस्तांतरण विलेख जो सम्यक् रूप से मुद्रांकित एवं पंजीकृत हों, जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है, के अभाव में स्थावर संपत्ति में कोई भी अधिकार, हक या हित

अंतरित नहीं हो सकता।

(29) चक्षुदर्शी साक्षी के आचरण एवं व्यवहार का परीक्षण इस कसौटी पर किया जाना चाहिए कि क्या उसका व्यवहार स्वाभाविक एवं संभावित है।

(30) यदि न्यायालय द्वारा एक मात्र साक्षी का अभिकथन विश्वसनीय पाया जाये, दोषसिद्धी का आधार हो सकता है।

Q.5- Translate the following 30 Sentences into Hindi :-
निम्नलिखित 30 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :– **–30**

(1) No application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed rejection.

(2) There shall be no discrimination against a child on any grounds including sex, caste, ethnicity, place of birth, disability and equality of access, opportunity and treatment shall be provided to every child.

(3) No person shall be eligible for selection as a member of the Board, if he has any past record of violation of human rights or child rights.

(4) It is well settled that the substantive evidence is the evidence of identification in court and the test identification parade provides corroboration to the identification of the witness in court, if required.

(5) It is necessary to reiterate that the multiplier method is logically sound and legally well established.

(6) The proposition of law is no longer res integra that the person who alleges breach must prove the same.

(7) The courts should be extremely careful and cautious in granting ex-parte ad-interim injunctions or stay orders.

(8) Pleadings are the foundation of the claims of parties. Civil litigation is largely based on documents.

(9) It is an irony that while we are celebrating women rights in all spheres, we show little or no concern for her honour. It is a sad reflection of the attitude of indifference of the society towards the violation of human dignity of the victims of sex crimes.

(10) Law in this behalf is absolutely clear. What cannot be done directly cannot be done indirectly.

(11) A civil court does not grant leave to file another suit. If the law permits, the plaintiff may file another suit.

(12) In absence of additional evidence, if Appellate Court concludes that trial's court order is not in accordance with law, then it should decide the matter by itself only and must not remand the matter simply for rewriting the judgment.

(13) Where the rules are silent, then the gap can be filled up by issuing executive instructions, however such instructions can only supplement the rule, but cannot supplant the rule.

(14) Plaintiff is not required to make out a clear legal title but has only to satisfy the court that he has fair question to arise as to existence of legal right claimed by him in suit.

(15) Court cannot take into consideration external materials given by accused for arriving to a conclusion that no offence was disclosed or there was possibility of acquittal.

(16) By seeking amendment, petitioner has not tried to set up a new case, only consequential relief was sought by him, which was already in substance in the suit in another form.

(17) An order affecting fundamental right or legal right of a citizen, is not an interlocutory order and revision is maintainable against

it.

(18) The Revisional Court while hearing a revision petition against an order dismissing a complaint is not obliged to hear the accused.

(19) FIR need not be an encyclopedia but is very vital material. It is the first information about incident in which there are less chance of alteration and improvement about the incident.

(20) Issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by one party and denied by the other.

(21) The parties cannot challenge the findings of the trial court before Appellate Court without filing cross objection against finding of trial court.

(22) Deciding the title arising out of Will is the domain of civil court only.

(23) At the last stage of defendant's evidence production of documents by the plaintiff should not be allowed specially where negligence of plaintiff is clear.

(24) Filling of an application under section 5 for condonation of delay before the court in writing is not mandatory. The court after using its discretion may condone delay even without written application.

(25) Without giving an opportunity to plaintiff for impleadment of a necessary party, suit cannot be dismissed on ground of non-joinder of necessary party.

(26) In Hindu Law, marriage is not a contract. Marriage cannot be performed by execution of a marriage affidavit.

(27) Revnue Court does not have any jurisdiction to dwell upon the question of title of a party. Civil rights of the party are to be determined by the civil court and not by the Revenue Court.

(28) A lessee has no right to sell the property which was leased by state in his favour because transfer of ownership rights is not included in lease.

(29) If there is a clear dispute of title, in absence of relief of declaration of title, the suit itself is not maintainable.

(30) When the parties sign a document, they can not wish away the consequences which flow from the signing of document.

*****